The Tribunal has since decided the cases in favour of government whereupon the offer of appointments to selected candidates have been made and many have since joined.

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए कल्याण योजनाएं

*247 **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लोगों की जीवनयापन संबंधी स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से कोई कल्याण कार्यक्रम आरंभ किए है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) और (ख) सरकार, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर के सर्वतोन्मुखी सुधार के लिए आदिवासी उप योजना और पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत बहुत से कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों में कृषि, शिक्षा, और होस्टल, सड़कें, पेयजल सप्लाई, सिंचाई और आवास आदि जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों सहित परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं। सातवीं योजना के दौरान, अनुसूचित जनजाति के 14,300 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी तुलना में, जून, 1988 के अन्त तक अनुसूचित जनजाति के 13964 परिवारों को पहले ही आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

1988–89 के दौरान, आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों के लिए राज्यों ने 2.04 करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था की है। जिसमें भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाने वाली 36.11 लाख रु० की धनराशि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, 1988–89 के दौरान, पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए 20.18 करोड़ रु० और खर्च किए जाएंगे।

Scheduled Castes Financial and Development Corporation

*248. SHRI V. GOPALSAMY:
SHRI T. R. BALU:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) when did Government set up Delhi Scheduled Caste Financial and Development Corporation;

(b) what are its aims and objectives;

(c) what activities and projects, it has since undertaken, giving details of each project, amount spent and results achieved;

(d) the number of employees and officials working in the Corporation; and how many of them belong to the scheduled castes; and

(e) whether the quote of SC/ST reservations has been filled; if not, what are the reasons therefor and what steps are proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WELFARE (DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI): (a) Delhi Scheduled Castes Financial and Development Corporation Limited was registered under the Companies Act on 29th January, 1983-(29-1-1983).

(b) The main aims and objectives of the Delhi Scheduled Castes Financial and Development Corporation are given in the enclosed statement-I (See below).